मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- मंदिर पर कब्जे की लड़ाई, प्रशासक ने सत्ता हथियाई 3
- सरकारी लूट के विरुद्ध ट्रांसपोर्ट हड़ताल
- स्त्री सुरक्षा और महिला थाना 4
- गतांक की चीर-फ़ाड़
- बिहार विधानसभा चुनाव : भगवा या नीतीश-लालू 5
- मेरे रहते शैतान लालू के पास-मोदी
- दोषी एसएचओ मारे मज़ा, निर्दोष एएसआई भोगे सज़ा 8

वर्ष 28 अंक 23 फरीदाबाद, शुक्रवार, 16-31 अक्टूबर 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

चाय बेचने का तो क्या पता, देश बेचने में मोदी का सानी नहीं

बिहार में मोदी-मोदी नहीं, दिल्ली-दिल्ली होगा

क्या बिहार में दिल्ली दोहराई जायेगी ? जिस तरह चुनाव प्रचार में मोदी के मुंह से गाली-गलौज का झाग ज़्यादा और विकास का राग कमतर होता जा रहा है, आसार कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं। अगर कहीं केजरीवाल की तरह नितीश कुमार भी चुनावी मैदान में अकेले अपने दम निकल पड़े होते तो भाजपा को दिल्ली की ही तर्ज़ पर करारी धूल चटा सकते थे। अब भी, यानी लालू और कांग्रेस के उन पर अतिरिक्त बोझे के बावजूद, भाजपा की हार निश्चित नज़र आ रही है। विडम्बना यह कि दिल्ली में बलि का बकरा किरण बेदी को बनाया गया था पर बिहार में मोदी-शाह को यह कवच उपलब्ध नहीं होगा।

मज़दूर मोर्चा, पटना से

नितीश कुमार के बनाये मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो अब भाजपा की गोदी में बैठे हैं, से भाजपा ने पलटवार में कहलवाया-''जहां पेड़ नहीं होता, वहां लोग कैकटस को पेड़ कहते हैं। नितीश अंधों में काना राजा हैं।'' मांझी का कहना कुछ हद तक ठीक हो सकता है लेकिन समस्या यह है कि भाजपा गठबंधन में तो अंधे ही अंधे भरे पड़े हैं-कोई काना भी नहीं। विकास के नाम पर मोदी अपनी केन्द्र सरकार का एक भी कारनामा नहीं गिना पा रहे हैं। उनके लगुए-भगुए मध्यप्रदेश की भाजपाई सरकार की उपलब्धियों का गुणगान जरूर करते हैं। इसके व्यापमं के ट्रैक रिकार्ड की गूंज नेपथ्य में चल ही रही है। इस बीच वहां चपरासी के 1333 पदों के लिये आवेदन मांगे गये और 4 लाख से ज़्यादा लोग कतार में खड़े मिले। इनमें 62000 स्नातक और 15000 बीटेक (इन्जीनियर) के अलावा सैंकड़ों पीएचडी भी शामिल हैं।

मोदी बोले तो बोलेंगे-13 साल में मध्यप्रदेश का इतना विकास किया। बोलो बिहार में ऐसा विकास चाहिये कि नहीं? भाइयो-बहनो बिहार में ऐसा विकास चाहिये कि नहीं? चाहिये कि नहीं?? चाहिये कि नहीं??? चाहिये कि नहीं???? ध्यान रहे कि यह बाजीगरी मोदी ने दिल्ली विधान सभा चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल की थी और बुरी तरह मुंह की खाई थी।

मोदी और भाजपा की हताशा का ही

नमूना है कि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और ओवैसी की एमआईएम को भी चुनावी मैदान में क्रमश: यादवों और मुसलमानों के वोट काटने के लिये उतारा गया है। हालांकि वोटर अब इतना समझदार हो चुका है कि किसी को भी 'वोट कटवा' बनने का मौका नहीं देने जा रहा। मोदी का अगला दांव गाय की पूंछ पकड़ कर वैतरणी पार करने का है। इस मकसद से पड़ोस के उत्तर प्रदेश को गौ-हत्या का मुद्दा गर्म रखने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ़ स्वयं मोदी को शर्मशार करने वाले कई आंकड़े निकल कर बाहर आ रहे हैं। उनकी सरकार के प्रयासों से गौमांस का निर्यात बढता जा रहा है, जिसका जवाब न मोदी के पास है और न भाजपा के।

इसी तरह महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर सिवाय खोखले वायदों के कोई रोड-मैप मोदी के भाषणों से प्रकट नहीं हो पा रहा। प्रकट हो भी कहां से जब है ही कुछ नहीं। सारी नीतियां मुनाफ़ाखोरों के ध्यान में रख कर बनाई जा रही हैं। रही सही कसर मोहन भागवत के आरक्षण विरोधी बयान ने पूरी कर दी है। भाजपा की ओर से आरक्षण बनाये रखने को लेकर सफ़ाइयां तो दी जा रही हैं पर मतदाता को 'मन की बात' करने वाले की असली नीयत समझ में आ चुकी है।

भाजपा अपने अभियान को अधिकतर लालू-केन्द्रित बनाये हुए है। पूर्व के लालू शासन को 'जंगलराज' कहकर लोगों को डराया जा रहा है। हालांकि तब से काफ़ी पानी गंगा से बहकर बंगाल की खाड़ी में जा चुका है। लालू-शासन को जंगलराज कहने वालों के अपने तर्क हो सकते हैं पर उस दौर में बिहार में अल्पसंख्यक जितना सुरक्षित रहा, उसकी कोई मिसाल स्वतन्त्र भारत में नहीं मिलती। सन् 1984 के सिख-संहार और 2002 के गुजरात पोग्राम जैसी शासन नियोजित बर्बरता को अपवाद माना जा सकता है। तब भी देश में सैंकड़ों की संख्या में होने वाले छोटे-बड़े साम्प्रदायिक दंगे और दलित और स्त्री-अपमान की नियमित घटनायें किसी जंगलराज में ही संभव हैं। दरअसल इन मामलों में मोदी एवं अन्य राजनेताओं को बिहार के भूतपूर्व जेलयाफ़्ता मुख्यमंत्री लालू यादव से ही सीखना होगा।

माना जा रहा है कि बिहार में विकास का मुद्दा और जातिगत समीकरण चुनाव परिणाम को तय करने में निर्णायक होंगे। इन दोनों बिन्दुओं पर नितीश के नेतृत्व वाला महागठबंधन आगे चल रहा है। यह बढत चुनावी विजय में बदलने जा रही है। सिलिकॉन वैली में अप्रवासी भारतीयों के मार्फ़त देश बेचना एक बात है पर बिहार की धरती पर बार-बार बिहारियों को उल्लू नहीं बनया जा सकता।

ख़बर दार

बिहार में शासक अश्वमेध विजय पर निकले

लालू यादव से काल्पनिक साक्षात्कार

इस दौर में आम आदमी के लिये एक दीवाली भारी पड़ती है। उधर बिहार में अश्वमेधी चुनावी विजय पर निकले दिल्ली के शासक दो-दो दीवाली मनाने का सपना देख रहे हैं-एक नियमित दीवाली और और दूसरी चुनावी जीत की। इसे साकार करने के लिये गाय से लेकर दादरी तक को भुनाया जा रहा है। मोदी के एक मन्त्री ने अखलाक की हत्या को हादसा बता डाला। ऐसी सोच वालों को तो गांधी की हत्या पिकनिक लगती होगी। दूसरे भी पीछे नहीं हैं। तमाम राजनीतिक जीव अखलाख के घर इस तरह भागे गये मानो वहां से वे साम्प्रदायिक्ता के हल का पक्का नुस्खा देश को देंगे। बिहार चुनाव प्रचार की पृष्ठभूमि में लालू यादव से एक काल्पनिक साक्षात्कार।

म.मो.-लालू जी आपका 13 वर्ष का शासक भ्रष्टाचार और विकास विरोध के लिये जाना जाता है। फ़िर भला लोग आपको क्यों वोट देंगे ?

लालू-यह सब पुरानी बातें हैं जिन्हें मैं भी जानता हूं और लोग भी जानते हैं। इसी लिये जनता ने मेरी पार्टी को बार-बार हराया भी। लेकिन इस बार हम जीतने जा रहे है क्योंकि नरेन्द्र मोदी के डेढ साल के शासक ने उनके विकास के दावे की पोल खोल कर रख दी है। लोगों को पता चल गया है कि वे भी हम जैसे ही हैं। हमें फ़ायदा यह है कि उनके पास अमितशाह हैं और हमारे पास नितीश कुमार।

म.मो.-मोदी जी का आरोप है कि आपकी बदनामी के चलते ही शैतान ने आपको ढूंढा है।

लालू-अरे भाई शैतान की असली दोस्ती मोदी से ही तो है। उन्होंने ही तो शैतान को मेरे पीछे लगाया है।

म.मो.-आपने यहां तक कह डाला कि हिन्दू भी गाय खाते हैं ?

लालू-क्या गांधी जी गाय खाते थे जो इन हिन्दुत्व के ठेकेदारों ने उनकी हत्या कर दी ? क्या दादरी में अखलाक के घर गोमांस था जो इन भाजपाइयों ने उसे मार डाला ? सवाल यह नहीं है कि लालू ने क्या कहा। ये चुनाव हार रहे हैं और हार का ठीकरा किसी न किसी पर तो फ़ोड़ना ही है। दिल्ली में किरण बेदी के सिर फ़ोड़ा था, बिहार में लालू की गाय के सिर फ़ोड़ देंगे।

म.मो.-मोदी जी दो दीवाली मनाने की बात कर रहे हैं। इस हिसाब से आप तो एक भी दीवाली नहीं मना पायेंगे।।

लालू-अरे हम दीवाली मना-मना कर थक चुके हैं। अब हम कुर्सी चाहते हैं। मोदी को जितना दीवाली मनाना हो मना लें। हम उन्हें फल-मिठाई उपहार जितना कहें भेज देंगे। उन्होंने बिहार के लिये 'पैकेज' की घोषणा की है। क्या हम उन्हें दीवाली पर पैकेट भी नहीं दे सकते ?

म.मो.-लालू जी आपने परिवार मोह नहीं छोड़ा। पत्नी और बेटी के बाद अब आपने अपने दो बेटों को भी राजनीति में उतार दिया।

लालू-सभी की किस्मत मोदी वाली नहीं हो सकती। न कोई अगाड़ी न कोई पिछाड़ी बस दौड़ती रहे गाड़ी। हमें तो बाल-बच्चों को भी धकेलना होता है। 'क्रिकेट' में नहीं चले तो राजनीति में सही।

नारियल फ़ोड़े बिना चालू हुआ मेडिकल कॉलेज

फ़रीदाबाद (म.मो.) फ़रवरी 2009 से 'निर्माणाधीन' रहे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का आखिर 5 अक्तूबर को विधिवत न सही पर समारोहपूर्वक उद्घाटन हो गया। उद्घाटन की विशेषता यह रही कि शहर भर की गलियों में नारियल फ़ोड़ने के अवसर खोजते तथाकथित नेताओं में से कोई भी यहां नज़र नहीं आया। विदित है कि शहर भर में सरकारी पैसे से चाहे नाली बने या नाला, सड़क बने या पुल, कोई न कोई 'नेता' नारियल फ़ोड़ने जरूर पहुंचा रहता है। कई बार तो नारियल फ़ोड़ने के इस अधिकार को लेकर इन 'नेताओं' में अच्छी खासी झड़प भी होती है। कुछ मामलों में तो एक के नारियल फ़ोड़ने के कुछ देर बाद दूसरा भी अपने चमचों के साथ पहुंच कर नारियल फ़ोड़ते फ़ोटो खिंचाता है।

दरअसल नारियल फ़ोड़ने की इस होड़ एवं रस्म -अदायगी के पीछे 'नेताओं' का आशय जनता को जताना होता है कि अमुक (सड़क या नाली) का काम उसीने कराया है, वरना यह होने वाला था नहीं। जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न होती है। किसी भी काम की योजना विभिन्न सरकारी विभाग समयानुसार बनाकर कार्यन्वित करते हैं। काम पूरा होते ही 'नेतागण' नारियल लेकर पहुंच जाते हैं।

भारत सरकार के उपक्रम ईएसआईसी द्वारा करीब एक हज़ार करोड़ की लागत से एनआईटी के एनएच-3 में बने इस अति महत्वपूर्ण परियोजना के उद्घाटन पर कोई नारियल वाला ठीक ही नहीं पहुंचा। दरअसल यहां के नेताओं की शुरू से ही इस प्रोजेक्ट में कोई रूचि नहीं रही क्योंकि यह मज़दूरों से सम्बन्धित है जिनके वेतन से हर माह साढे 6 प्रतिशत ईएसआई निगम काट लेता है। बेशक इस कॉलेज-अस्पताल से फ़रीदाबाद के 5 और गुड़गांव के 9 लाख मज़दूर परिवारों को सीधा लाभ होने वाला है; लेकिन ये मज़दूर उक्त नेताओं की प्राथमिकता में कहीं नहीं आते। नेताओं की इसी उदासीनता के चलते सन् 2012 में चालू होने वाला यह कॉलेज एवं अस्पताल 2015 में चालू हो पाया वह भी भारी कठिनाइयों से गुजरने के बाद। यदि शहर के इन नेताओं को इसके प्रति थोड़ी सी भी लग्न होती तो यह काम 3 वर्ष पूर्व ही हो सकता था।

उद्घाटन अवसर पर ईएसआईसी के अधिकरी, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर व स्टाफ़, श्रमिक प्रतिनिधि, मेडिकल छात्रों के अभिभावक व आखीर में उपायुक्त भी शरीक हुए। उम्मीद है इस सुविधा के पूरी तरह चलने पर अन्य सरकारी अस्पतालों से 'लोड' कम होगा और श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

प्रथम सत्र में दाखिल होने वाले 100 छात्रों में से 3 बीमाकृत श्रमिकों के बच्चे हैं। इनमे से एक छात्रा जो दिल्ली से है, की विधवा मां ओखला की एक फ़ैक्ट्री में कार्यरत है। उनका मासिक वेतन मात्र 8000 रुपये है। वह इस स्थिति में भी नहीं थी कि फ़ीस के 54000 रुपये भर सके। ऐसे में कॉलेज फ़ैकल्टी ने अपने पल्ले से उनकी फ़ीस जमा करके एक मिसाल कायम की।